फा.सं.25-I(05)/2023-एएचडी/एआर

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

****

मई, 2023 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय एवं प्रमुख उपलब्धियां।

1. गोपशु और डेयरी विकास:

i. "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)" योजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 17.05.2023 को जारी की गई।

2. पशुधन स्वास्थ्य

i. लम्पी त्वचा रोग नियंत्रण में है, जनवरी, 2023 के महीने में मामले 183556 से घटकर मई, 2023 के महीने में 8271 हो गए हैं। सिक्किम, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब में लम्पी त्वचा रोग (एलएसडी) के पुनः प्रकोप की पुष्टि होने पर, विभाग ने एलएसडी के समय पर नियंत्रण और रोकथाम तथा रोग के आगे प्रसार को रोकने के लिए राज्य को परामर्शी और दिशानिर्देश दिए हैं। राज्य, परामर्शी के अनुसार आवश्यक कार्रवाई और उपाय कर रहे हैं।

ii. उत्तर प्रदेश राज्य में अफ़्रीकी स्वाइन फ़्लू (एएसएफ) के पुनः प्रकोप की पुष्टि होने पर, विभाग ने सूअरों में एएसएफ के तत्काल नियंत्रण और रोकथाम के उपायों को सख्ती से क्रियान्वित करने की सलाह के साथ परामर्शी और राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की।

iii. विभाग ने मेसर्स वेंकी (इंडिया) लिमिटेड पुणे के तीन प्रतिष्ठानों को विभाग के ओआईई दिशानिर्देशों और विशिष्टताओं के अनुरूप एएल-मुक्त के रूप में उनका मूल्यांकन करने और मान्यता देने के लिए महाराष्ट्र में एक एक तकनीकी विशेषज्ञों की टीम टीम तैनात की।

iv. विभाग ने रेबीज के नियंत्रण के लिए गोवा कार्य योजना में ओरल बैट वैक्सीन (ओबीवी) की निगरानी और मूल्यांकन के लिए गोवा में एक एक विशेषज्ञों की टीम तैनात की।

v. विभाग ने वर्ष 2030 तक कुत्तों के माध्यम से होने वाले रेबीज उन्मूलन के लिए राज्य कार्य योजनाएं (एसएपीआरई) विकसित करने के लिए दिनांक 18-19 मई, 2023 को उत्तर पूर्व राज्यों हेतु क्षेत्रीय कार्यशाला के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञों की टीम को तैनात किया।

vi. विभाग ने एलएसडी के संबंध में नियंत्रण और रोकथाम कार्यों के जमीनी स्तर पर पर्यवेक्षण और निगरानी तथा नियंत्रण और टीकाकरण दिशानिर्देशों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राज्य की सहायता हेतु एक तकनीकी विशेषज्ञों की टीम को उत्तराखंड में तैनात किया।

vii. 5 चिन्हित राज्यों (असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा) में विश्व बैंक समर्थित एएचएसएसओएच (AHSSOH) कार्यक्रम की वन हेल्थ केस स्टडी किया ।

viii. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) के तहत अब तक 25.16 करोड़ गोपशुओं और भैंसों को ईयर टैग किया जा चुका है। एफएमडी टीकाकरण के द्वितीय चरण में, पूरे देश में 24.18 करोड़ गोपशुओं और भैंसों को टीका लगाया गया है। कुल 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एफएमडी के द्वितीय चरण का टीकाकरण पूरा कर लिया है और समापन रिपोर्ट डीएएचडी के साथ साझा की है।

ix. कर्नाटक और केरल राज्य में एफएमडी टीकाकरण का तृतीय चरण पहले ही पूरा हो चुका है। यह 8 राज्यों नामत: महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। तृतीय चरण में अब तक 4.55 करोड़ टीकाकरण किया जा चुका है।

x. अब तक कुल 2.12 करोड़ पशुओं को ब्रुसेलोसिस का टीका लगाया गया है।

3. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम):

i. मई, 2023 माह के दौरान उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत कुल 77 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिनकी कुल परियोजना लागत 65.27 करोड़ रुपये है।

ii. दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए आईएमडी के पूर्वानुमान के मद्देनजर देश में चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले उपयुक्त उपायों/कदमों के संबंध में सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को एक परामर्शी जारी की गई है।

4. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी)

i. पशुधन और डेयरी सेक्टर के क्षेत्र में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सहित द्विपक्षीय सहयोग/व्यापार पर चर्चा करने के लिए दिनांक 9 मई, 2023 को सचिव, एएचडी और न्यूज़ीलैंड के विशेष कृषि व्यापार दूत सुश्री मेलानी पॉल्टन के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान 4-5 देशों के साथ ज्यादातर व्यापार संबंधी मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा हुई। टेबल अंडों के लिए यूएई एक बड़ा बाज़ार प्रतीत होता है। न्यूज़ीलैंड के साथ उनकी डेयरी विशेषज्ञता से सीखने के लिए ज्ञान के आदान-प्रदान पर चर्चा हुई।

ii. संयुक्त सचिव (आईसी/व्यापार) और भारत में ब्राजील दूतावास के कृषि अताशे श्री एंजेलो डी क्विरोज मौरिसियो के बीच दिनांक 24.5.2023 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की गई, जिसमें ब्राजील से भारत को हैचिंग अंडे तथा बोवाइन और ब्यूबलीन आनुवंशिकी सामग्री का निर्यात, भारतीय पेशेवरों का प्रशिक्षण आदि भी शामिल था। इसी तरह भारतीय पक्ष ने ब्राजील में भारतीय डेयरी उत्पादों और मांस उत्पादों की बाजार पहुंच का भी शुभारंभ किया।

iii. सचिव, एएचडी और पशुपालन आयुक्त, एएचडी ने दिनांक 21 से 25 मई, 2023 तक पेरिस, फ्रांस में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच) के राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की विश्व सभा के 90वें आम सत्र में भाग लिया।

iv. पशुपालन आयुक्त, एएचडी और विभाग के एक अधिकारी ने दिनांक 8-12 मई, 2023 के दौरान भूटान में आयोजित पहली दक्षिण एशिया सीमापारीय पशु रोग बैठक में भाग लिया।

v. सहायक आयुक्त (डेयरी) ने दिनांक 15 से 19 मई, 2023 तक कनाडा में आयोजित खाद्य लेबलिंग संबंधी कोडेक्स समिति के 47वें सत्र में भाग लिया।

vi. पशुपालन आयुक्त, एएचडी और विभाग के एक अधिकारी ने दिनांक 15 से 19 मई, 2023 तक न्यूजीलैंड में एमपीआई एप्लाइड महामारी विज्ञान व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

vii. सहायक आयुक्त (डेयरी) ने दिनांक 1 से 5 मई, 2023 तक ऑस्ट्रेलिया में खाद्य आयात और निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली पर कोडेक्स समिति के 26वें सत्र में भाग लिया।

5. क्रेडिट, विस्तार और प्रचार(सीईपी):

आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री परशोत्तम रूपाला ने दिनांक 03 मई 2023 को सुबह 9:30 बजे वर्चुअल मोड के माध्यम से आधिकारिक तौर पर वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान शुरू किया और लाभार्थियों के साथ बातचीत की। एएचडीएफ-केसीसी सीएससी और राज्य पशुपालन विभाग के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यह कदम पशुपालन और मत्स्यपालन कार्यकलापों में लगे सभी छोटे भूमिहीन किसानों को केसीसी सुविधा प्रदान करने में मदद करेगा।

देश के सभी पात्र पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन करने वाले किसानों तक किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पहुंचाने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन विभाग (डीओएफ) वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सहयोग से दिनांक 1 मई 2023 से 31 मार्च 2024 तक "राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान" का आयोजन कर रहा है। इस अभियान के आयोजन के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों से अवगत कराने वाला परिपत्र दिनांक 13.03.2023 को राज्यों को जारी किया गया है। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के साथ-साथ राज्य सरकार को भी आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।

6. बजट:

वर्ष 2023-24 के लिए मई, 2023 तक 4687.85 करोड़ रुपये के बजट अनुदान के मुकाबले व्यय 72.09 करोड़ रुपये था। मई, 2023 के दौरान, पशुपालन और डेयरी विभाग का व्यय 37.71 करोड़ रुपये था।

7. शिकायत निपटान

सीपीजीआरएएम पोर्टल के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग का शिकायत निवारण 99% है।

******